# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31—फरवरी 6, 2015 (माघ 11, 1936)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31—FEBRUARY 6, 2015 (MAGHA 11, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची पुष्ठ सं. पृष्ठ सं. भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोडकर) भारत सरकार के प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकत पाठ (ऐसे पाठों को छोडकर जो भारत अधिसूचनाएं. ..... के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों होते हैं)..... और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी नियम और आदेश..... अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नितयों, भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ..... महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल 233 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... अधिसूचनाएं. ..... भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और के बिल तथा रिपोर्ट. ..... डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं...... प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों छोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक द्वारा जारी की गई अधिसचनाएं, आदेश, विज्ञापन नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और और नोटिस शामिल हैं..... उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों 65 (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को को दर्शाने वाला सम्पुरक. .....

(11)

## **CONTENTS**

	Page No.		Page No.
Part I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and		by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	11	Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than	
the Supreme Court		Administration of Union Territories)	*
and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	Attached and Subordinate Offices of the	
Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations		Government of India  Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	
Committee on Bills		PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	
Administration of Union Territories)		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private	
Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the		Individuals and Private Bodies	65
Ministries of the Government of India		Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	
(other than the Ministry of Defence) and		Deanis etc. both in Eligibil and Hiller	*

<sup>\*</sup>Folios not received.

# भाग I \_ खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं।
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जनवरी 2015

संकल्प

विषय:--भूमि जल प्राक्कलन पद्धति, 1997 (जीईसी-97) की समीक्षा और संसोधन के लिए भूमि जल प्राक्कलन समिति का गठन।

सं. टी.-13014/4/2014-जीडब्ल्यू--भूमि जल प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए क्षेत्रों का पता लगाने और प्राथमिकता तय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमि जल विभाग संयुक्त रूप से नियमित अन्तराल पर ''भूमि जल प्राक्कलन समिति 1997'' (जीईसी 97) द्वारा संस्तुत पद्धित के आधार पर देश के भूमि जल संसाधनों का आकलन करते हैं। वर्ष 2004, 2009 और 2011 में जीईसी-97 के अनुसार भूमि जल आकलन किया गया था।

2. जीईसी, 97 को अपनाए जाने से अब तक केद्रीय भूमि जल बोर्ड, राज्य भूमि जल संगठन, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों ने भूमि जल संसाधनों के आकलन के लिए कई अध्ययन किए हैं। विभिन्न परामर्शी बैठकों और कार्यशालाओं में अध्ययनों के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया और उन पर विचार विमर्श किया गया। भूमि जल मॉडिलंग जैसी नई तकनीकों/पद्धितयों/तौर-तरीकों को शामिल करने और आकलन में उपयोग किए जा रहे विभिन्न पैरामीटरों को बेहतर बनाने के लिए जीईसी-97 की समीक्षा और उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

### 3. समिति का गठन:

उपर्युक्त को देखते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार भूमि जल प्राक्कलन पद्धति (जीईसी-97) की समीक्षा और संशोधन तथा तत्संबंधी मुददों पर कार्रवाई करने के लिए एतदुद्वारा एक समिति का गठन करता है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएसएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), स्टर्लिंग सेंटर, शिव सागर एस्टेट, डॉ. एनी बेसेंट रोड, पोस्ट बैग नं. 6552, मुंबई-400018	सदस्य
4.	उप महानिदेशक, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, सीजीपीबी सिचवालय, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, पुष्पा भवन, ए-ब्लॉक, दूसरा तल, मदनगीर रोड, नई दिल्ली-110062	सदस्य
5.	निदेशक, राज्य जल अन्वेषण निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, सिचवालय भवन (तीसरा तल), साल्ट लेक, कोलकाता-700091	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), राज्य भूमि एवं सतही जल संसाधन आंकड़ा केन्द्र तिमलनाडु सरकार, आईडब्ल्यू एस परिसर तारामनी, चेन्नई–600113	सदस्य
7.	अधीक्षण भू-जल विज्ञानी, मध्य प्रदेश सरकार, भूमि जल सर्वेक्षण परिमंडल, भोपाल (मध्य प्रदेश)	सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, गुजरात जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड, गुजरात सरकार, सेक्टर-10ए, ब्रिज भवन के समीप गांधी नगर-382043	सदस्य
9.	निदेशक, राज्य भूमि जल विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, बीआरकेआर परिसर, 7वां और 8वां तल, बी-ब्लॉक, टैंक बंड रोड, हैदराबाद-500063	सदस्य
10.	निदेशक, भूमि जल सर्वेक्षण और विकास अभिकरण, महाराष्ट्र सरकार, भू–जल भवन, शिवाजी नगर, पुणे–411005	सदस्य
11.	निदेशक, जल संसाधन एवं पर्यावरण निदेशालय, पंजाब सरकार, एससीओ 32-34, सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़-160017	सदस्य
12.	निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि जल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 9वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001	सदस्य
13.	सदस्य (टीटी एवं डब्ल्यूक्यू), सीजीडब्ल्यूबी, एनएच-IV, फरीदाबाद	सदस्य सचिव

- 3.1 विशेष आमंत्रित अधिकारी/गणमान्य व्यक्ति
- 1. आयुक्त (एसपी) भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
- 2. प्रमुख, भूमि जल विज्ञान प्रभाग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन, रुड़की-247667
- 3. प्रो. डॉ. एन. जे. राजू, पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- 4. प्रो. डॉ. ए. के. गोसाई, सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली।
- 5. डॉ. एस. के. श्रीवास्तव, आईआईआरएस, अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार, कालीदास रोड, देहरादुन-248001
- 6. डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, जल संसाधन विकास और प्रबंधन उन्नत केन्द्र, पुणे, महाराष्ट्र।
- 7. सदस्य (एसएएम), केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, एनएच-IV, फरीदाबाद।
- 8. सदस्य (एसएमएल) और सदस्य-सचिव, सीजीडब्ल्यूए, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
- 3.2 श्री राणा चैटर्जी, वैज्ञानिक-घ, सीजीडब्ल्यूबी इस सिमिति का सहयोग करेंगे।
- 3.3 सिमिति आवश्यकता होने पर किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) का चयन कर सकती है।
- 4. विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:--

- 1. विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए वैज्ञानिक कार्य के आधार पर भूजल संसाधन के आकलन में वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्राचलों और उनके मान का निर्धारण करना/अद्यतन करना।
- 2. भूजल आकलन समिति (1997) द्वारा पद्धित के संबंध में की गई सिफारिशों के ब्योरे की जांच करना और उन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना जिनमें संशोधन की आवश्यक है। सिमिति आवश्यकता समझे जाने पर विभिन्न जल भूवैज्ञानिक स्थितियों और जलवायु जोन में भूजल संसाधन के आकलन के लिए वर्तमान पद्धित को अद्यतन कर सकती है अथवा नई पद्धित की सिफारिश कर सकती है।
- 3. जल भूवैज्ञानिक/जल वैज्ञानिक और/अथवा प्रशासनिक प्रभाग के आधार पर भूजल संसाधन के आकलन के लिए सबसे छोटी आकलन इकाइयों की सिफारिश करना।
- 4. शहरी क्षेत्रों/विशिष्ट क्षेत्रों में भूजल संसाधन के आकलन के लिए पद्धति की सिफारिश करना।
- भूजल संसाधन के तत्काल आकलन के लिए वैकल्पिक पद्धितियों का सुझाव देना।
- 6. सिमिति को भूजल संसाधन के आकलन में गुणवत्ता मानक समाविष्ट करने के लिए रीतियों एवं पद्धतियों का सुझाव देना चाहिए।
- कुल भूजल उपलब्धता के आकलन के लिए पद्धित की समीक्षा करना एवं सिफारिश करना।
- उपर्युक्त शर्तों से संबंधित कोई अन्य पहलू।
- समय-सीमा :

समिति, संकल्प जारी होने की तारीख से 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

6. व्यय:

समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय दिनांक 23.09.2008 के वित्त मंत्रालय के का. ज्ञा. सं. 19030/3/2008-ई-IV में दिए गए निर्देशों और मितव्ययिता, यात्रा प्रतिबंधों आदि के संबंध में समय-सयम पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उस स्रोत से वहन किया जाएगा जिससे उनका वेतन आहरित किया जाता है और गैर-सरकारी सदस्यों (यदि कोई हो) का व्यय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

इसे माननीय मंत्री ((ज.सं., न. वि. और गं. सं.) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रकाशित संकल्प की एक प्रति इस मंत्रालय को भेजी जाए।

> आर. के गुप्ता निदेशक (जीडब्ल्यू)

### MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

New Delhi-110 001, the 7th January 2015

### RESOLUTION

Sub:— Constitution of Ground water estimation Committee to review and revise the Ground Water Estimation Methodology 1997 (GEC-97).

No. T-13014/4/2014-GW—The ground water resources assessment of the country is being carried out jointly by Central Ground Water Board and State Ground Water Departments based on methodology recommended by "Ground Water Estimation Committee 1997" (GEC 1997) at regular interval with the objective to identify and prioritize the areas for ground water management interventions. The ground water assessments in 2004, 2009 and 2011 were done as per GEC-97.

(2) The Central Ground Water Board, State Ground Water Organisation, Universities and other organisations have carried out number of studies on assessment of ground water resources since the GEC-97 was adopted. Results of the studies were presented and deliberated in various consultative meetings and workshops. A need was felt to review and revise the GEC-1997 methodology to incorporate new advancements/practices/tools like ground water modelling and also refining the various parameters being used in assessment.

### (3) Composition of the Committee:

In the view of above, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India hereby constitutes a committee to review and revise the Ground water Estimation Methodology (GEC-97) and look into related issues. The Committee will consist of following Members:

1.	Chairman, Central Ground Water Board	Chairman
2.	Joint Secretary (WSM), Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi.	Member
3.	General Manager, National Bank for Agriculture, & Rural Development (NABARD), Sterling Centre, Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Post Box No. 6552, Mumbai -400 018	Member
4.	Dy. Director General, Geological Survey of India, CGPB Secretariat, Geological Survey of India, Pushpa Bhawan, A-Block, 2nd Floor, Madangir Road, New Delhi - 110062.	Member
5.	Director, State Water Investigation Directorate, Government of West Bengal, Sectt. Bhawan (3rd Floor), Salt Lake, Kolkata - 700 091.	Member
6.	Chief Engineer (PWD), State Ground and Surface Water Resources Data Centre, Water, Government of Tamil Nadu, IWS Campus, Tharamani, Chennai - 600 113.	Member
7.	Superintending Geohydrologist, Government of Madhya Pradesh, Ground Water Survey Circle, Bhopal (MP).	Member
8.	Managing Director, Gujarat Water Resources Development Corporation Ltd., Government of Gujarat, Sector-10 A, Near Bij Bhawan, Gandhinagar - 382043.	Member
9.	Director, State Ground Water Department, Government of Andhra Pradesh, B.R.K.R. complex, 7th and 8th Floor, B-Block, Tank Bund Road, Hyderabad - 500063.	Member
10.	Director, Groundwater Survey and Development Agency, Government of Maharashtra, Bhujal Bhawan, Shivaji Nagar, Pune - 411 005.	Member
11.	Director, Water Resources & Environment Directorate, Government of Punjab, SCO- 32-34, Sector-17C Chandigarh 160017	Member
12.	Director, UP Ground Water Department, Government of Uttar Pradesh, 9th Floor, Indira Bhavan, Ashok Marg, Lucknow - 226 001.	Member
13.	Member(TT&WQ), CGWB, NH-IV, Faridabad	Member Secretary

- 3.1 Special Invitees:-
- 1. Commissioner (SP), Government of India, MOWR, RD&GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi 110 001.
- 2. Head, Ground Water Hydrology Division, National Institute of Hydrology, Jalvigyan Bhawan, Roorkee 247667
- 3. Professor Dr. N. J. Raju, School of Environmental Sciences, Jawaharlal University, New Delhi
- 4. Professor Dr. A.K. Gosai, Department of Civil Engineering, IIT Delhi
- 5. Dr. S. K. Srivastav, IIRS, Dept. of Space, Govt. of India, Kalidas Road, Dehradun 248 001
- 6. Dr. Himanshu Kulkarni, Advanced Centre for Water resources development and Management, Pune, Maharashtra
- 7. Member(SAM), Central Ground Water Board, NH-IV, Faridabad
- 8. Member (SML) and Member Secretary, CGWA, R.K. Puram, New Delhi
- 3.2 Sh. Rana Chatterjee, Scientist-D, CGWB, will assist the Committee.
- 3.3 The committee may co-opt any other Member(s), if necessary.
- 4. Terms of reference

The terms of reference of the Committee are as follows:

- 1. Firming up / updating various parameters and their values currently used in the assessment of ground water resources based on the scientific work carried out by various organizations.
- 2. To look into the details of the methodology recommended by Ground Water Estimation Committee (1997) and to suggest aspects which call for a revision. The Committee may, if considered necessary, update the existing or recommend a new methodology for the assessment of ground water resources in different hydrogeological situations and climatic zones.
- 3. To recommend the smallest assessment unit for assessment of ground water resources based on hydrogeological/hydrological and/or administrative division.
- 4. To recommend a methodology for assessment of ground water resource in urban areas/specific areas.
- 5. Suggest alternative approaches for real time assessment of ground water resources.
- 6. Committee should suggest modality and methodology for incorporating quality consideration in assessment of ground water resources.
- 7. Review and recommend methodology for assessment of Total Ground Water Availability.
- 8. Any other aspects relevant to the terms referred to above.
- 5. Time frame:

The Committee may submit its report within 6 month from the date of issue of resolution.

### 6. Expenditure

Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Committee will be met from the source from which they draw their salaries and that of non-official Members (if any), will be borne by the Central Ground Water Board, subject to the directions indicated in MoF OM No. 19030/3/2008-E.IV dated 23.09.2008 and directions issued by MoF from time to time in relation to austerity, travel restrictions etc.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister (WR,RD&GR).

### **ORDER**

Ordered that the above RESOLUTION be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution published be communicated to this Ministry.

R.K. GUPTA Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015 www.dop.nic.in